

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 02]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 जनवरी 2025—पौष 20, शक 1946

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 दिसम्बर 2024

क्रमांक एफ 5-3/2024/एक (1).—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री राधाकिशन अग्रवाल, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 03-10-2024 से दिनांक 08-10-2024 तक कुल (06 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश तथा अवकाश पूर्व दिनांक 02-10-2024 का सार्वजनिक अवकाश एवं अवकाश पश्चात् दिनांक 09-10-2024 से 13-10-2024 तक के दशहरा अवकाश के लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्लेमेन्टीना लकड़ा, अवर सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 2 दिसंबर 2024

क्रमांक एफ 16-1/2016/विविध/गृह-दो.—राज्य शासन एतद्वारा 01 नवम्बर, 2024 राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर “छत्तीसगढ़ शौर्य पदक नियम, 2017” अन्तर्गत निम्नांकित राज्य पुलिस बल कार्मिकों को वर्ष 2024 के लिए “छत्तीसगढ़ शौर्य पदक” प्रदान किया जाता है :—

1.	श्री देवांश सिंह राठौर, उप पुलिस अधीक्षक	जिला-दन्तेवाड़ा.
2.	श्री रंजन मरकाम, प्रधान आरक्षक-761,	जिला-बीजापुर.
3.	श्री सोमलू ताती, आरक्षक-585,	जिला-बीजापुर,
4.	श्री संजीव कुंजाम, प्रधान आरक्षक-128,	जिला-गरियाबंद,
5.	श्री थानूराम ठाकुर, आरक्षक-221,	जिला-गरियाबंद,
6.	श्री अशोक भार्गव, आरक्षक-793,	जिला-गरियाबंद.
7.	श्री विष्णु नेताम, आरक्षक-2041,	जिला-धमतरी.
8.	श्री संतराम कोसरे, आरक्षक-2027,	जिला-धमतरी.
9.	श्री गणेश्वर सोरी, आरक्षक-2033,	जिला-धमतरी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. कौशल, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 27 नवम्बर 2024

क्रमांक एफ 20-32/2024/11/(6).—चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत कंडिका 15.13, 15.21 एवं परिशिष्ट-6.19, के अनुसरण में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के माध्यम से राज्य में वृहद, मेगा, अल्ट्रा मेगा उद्योगों की स्थापना हेतु राज्य में “सीमेंट उद्योग क्षेत्र” में निवेश हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज का निर्धारण निम्नानुसार करता है :—

मेगा निवेशकों के लिए Be Spoke Policy के अन्तर्गत सीमेंट सेक्टर की इकाईयों के मेगा/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स की स्थापना हेतु प्रस्तावित विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज की सामान्य नियम व शर्तें :—

- (1) औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के लिए सीमेंट सेक्टर को कोर सेक्टर की श्रेणी में रखा गया है. राज्य में सीमेंट संयंत्र की स्थापना हेतु राज्य सरकार के साथ एमओयू निष्पादित कर चुकी इकाईयों में से 02 इकाईयों के द्वारा उत्पादन प्रारंभ किया जा चुका है. संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित तालिका पर दर्शित है.

क्र.	इकाई का नाम एवं पता	एमओयू दिनांक	प्रस्तावित पूंजी निवेश (करोड़ में)	उत्पादन प्रारंभ दिनांक	स्थल	औद्योगिक नीति 2019-24 अनुसार विकासखण्ड की श्रेणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, मुम्बई (विस्तार परियोजना)	06-08-2021	954	30-04-2022	ग्राम हिरमी तह-सिमगा, बलौदाबाजार	श्रेणी-अ

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, मुम्बई (नवीन परियोजना)	06-08-2021	1500	02-04-2024	ग्राम सकरीपार, तह-सिमगा, बलौदाबाजार	श्रेणी-अ

- (2) औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत पूर्व में राज्य शासन द्वारा अन्य कोर सेक्टर उद्योगों के लिए स्वीकृत पैकेज में “अ” श्रेणी के विकासखंडों में इस योजना के अंतर्गत घोषित किए जा रहे पैकेज में प्रत्येक इकाई द्वारा प्रस्तावित निवेश के आधार पर कुल देय पैकेज में कुल निवेश के 60 प्रतिशत के बराबर (6 प्रतिशत प्रतिवर्ष अधिकतम की सीमा तक) अधिकतम आर्थिक निवेश प्रोत्साहन हेतु 10 वर्ष के लिए पात्रता होगी अथवा पैकेज की अधिकतम मान्य सीमा राशि रुपये 500 करोड़ तक जो भी कम हो “विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज” की पात्रता मान्य किया जाना अनुशंसित है. पैकेज में उल्लेखित समस्त अनुदान, छूट व रियायतें इस सीमा के अंतर्गत ही देय होंगी. इस पैकेज में प्रश्नाधीन सेक्टर के लिये निम्नलिखित अनुसार पैकेज दिये जाने की अनुशंसा की जाती है :—

(2.1) **नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति :—**

औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से राज्य को भुगतान किए गए नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर की प्रतिपूर्ति निम्नानुसार होगी :—

क्र.	विकासखण्डों की श्रेणी	प्रतिपूर्ति की अधिकतम अवधि	अधिकतम सीमा
1	श्रेणी-अ	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष तक वार्षिक आधार पर देय होंगी.	अधिकतम स्थायी पूंजी निवेश के 35 प्रतिशत तक

(2.2) **विद्युत शुल्क छूट :—**

उपरोक्त बिन्दु में सम्मिलित सीमेंट सेक्टर के उद्यमों को निम्नलिखित विवरण अनुसार विद्युत शुल्क छूट दिये जाने की अनुशंसा की जाती है :—

क्र.	विकासखण्डों की श्रेणी	विवरण
1	श्रेणी-अ	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष.

(2.3) **स्टाम्प शुल्क से छूट :—**

औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत राज्य में सीमेंट सेक्टर के नवीन उद्यम की स्थापना तथा विद्यमान उद्यमों के विस्तार/शक्तीकरण/प्रतिस्थापन के प्रकरणों में भूमि, शेड तथा भवनों के क्रय/पट्टे पर लिए जाने के मामले में निष्पादित किये जाने विलेखों पर संबंधित भूमि लीज के विलेखों पर स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान किया जायेगा.

टीप :— जिन इकाईयों के द्वारा भूमि का इकाई के नाम पर पंजीयन कराया जा चुका है तो इकाई द्वारा भुगतान की गई राशि नियमानुसार वापसी योग्य नहीं है. साथ ही इसकी प्रतिपूर्ति भी नहीं की जाएगी.

(2.4) **दिव्यांग (निःशक्त) रोजगार व्यय प्रतिपूर्ति अनुदान :—**

औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत सीमेंट सेक्टर के पात्र नवीन उद्यम की स्थापना तथा विद्यमान उद्यमों के विस्तार/शक्तीकरण/प्रतिस्थापन के प्रकरणों में दिव्यांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान उत्पादन दिनांक से पांच वर्ष तक के लिए की पात्रता होगी.

- (3) रायपुर जिले के विकासखंड अभनपुर, धरसीवा एवं आरंग को छोड़कर राज्य के अन्य क्षेत्रों में पूर्व से स्थापित विद्यमान इकाईयों में विस्तार/शक्तीकरण/प्रतिस्थापन के लिये अतिरिक्त निवेश करने पर इकाईयों प्रस्तावित आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु तभी पात्र होंगे, जब वे अपनी वर्तमान स्थापित क्षमता में कम से कम 50 प्रतिशत की वृद्धि करें एवं स्थायी पूंजी निवेश में पूर्व में निवेशित राशि का कम से कम 100 प्रतिशत अतिरिक्त निवेश करें.
- (4) जिन मदों में आर्थिक निवेश प्रोत्साहन दिया जाना है उनमें इकाई के द्वारा वार्षिक आधार पर मदवार भुगतान की गई/व्यय की गई राशि से अधिक निवेश प्रोत्साहन (अनुदान, छूट, रियायतें) दिया जाना मान्य नहीं होगा.

- (5) इस पैकेज में घोषित आर्थिक निवेश प्रोत्साहन तभी प्राप्त होगी जब नवीन इकाई में कम से कम 100 करोड़ रुपयों का स्थायी पूंजी निवेश मद में निवेश कर व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ करें.
- (6) प्रकरण में उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार पैकेज का अनुमोदन किया गया है. इस पैकेज में संक्षेपिका की कंडिका क्रमांक (9) में उल्लेखित अनुदान/छूट/रियायतों के साथ ही औद्योगिक नीति 2019-24 में वर्णित अन्य अनुदान/छूट/रियायतों हेतु नियमानुसार पात्रता होंगी, किन्तु किसी भी अवस्था में अनुदान/छूट/रियायतों की कुल राशि कंडिका क्रमांक (3) में वर्णित अनुदान की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी.
- (7) इस पैकेज के यथा आवश्यक विस्तृत दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे.

यह अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 नवम्बर 2024

संशोधन

क्रमांक 4109/3979/21-ब/छ.ग./2024.—श्रीमती गीता नेवारे, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जशपुर के सेवानिवृत्ति संबंधी इस विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 3889/3363/21-ब/छ.ग./2024 दिनांक 25-10-2024 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

उक्त आदेश के सरल क्रमांक 05 के कॉलम तीन में अंकित “16-07-2025” के स्थान पर “16-07-1965” पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शहाबुद्दीन कुरैशी, अतिरिक्त सचिव.

श्रम विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 नवम्बर 2024

क्रमांक एफ-10-1/2019/16.—कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का संख्या 63) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार, राज्य बीमा सेवाओं के कर्मचारियों के औषधालयों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र में स्थित कारखानों के लिए “शल्य चिकित्सक” के रूप में नियुक्त करती है. नियुक्त शल्य चिकित्सक ईएसआईएस औषधालय के किसी अन्य चिकित्सा अधिकारी को अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं.

No. F 10-1/2019/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Factories Act, 1948 (No. 63 of 1948)) and in supersession of all earlier notifications issued in this behalf, the State Government hereby appoints the Medical Officers in-Charge of the Dispensaries of the Employees of the State Insurance Services as “Certifying Surgeons” for the factories situated under their area of jurisdiction. The appointed “Certifying Surgeons” may authorize any other Medical Officer of the ESIS dispensary to exercise his powers under the Act.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फरिहा आलम, उप-सचिव.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 नवम्बर 2024

क्रमांक एफ 19-19/2024/54.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 08-08-2024 द्वारा छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अधिसूचना दिनांक 16 जुलाई 2024 की कंडिका-3 में निहित प्रावधान के तहत, अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति करते हुए पद ग्रहण करने की तिथि से, अधिनियम की कंडिका-4 के अनुसार कार्यकाल 03 माह किया गया था।

- राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग में नियुक्त अध्यक्ष/सदस्यों के कार्यकाल में 02 वर्षों की वृद्धि करता है।
- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 849, दिनांक 13-11-2024 के द्वारा प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, प्रमुख सचिव।

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 नवम्बर 2024

क्रमांक 900/एफ 1-1/2019/13/1.—सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-03/2024/एक-2 दिनांक 03-10-2024 से डॉ. रोहित यादव, भा.प्र.से. (2002) को सचिव, ऊर्जा के पद पर पदस्थ करते हुए अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

- अतः राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन/ट्रांसमिशन/डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम की कंडिका 77 (iv) के विहित प्रावधान के अनुशरण में श्री पी. दयानंद, भा.प्र.से. (2006) को उक्त कंपनी के निदेशक एवं अध्यक्ष के पद से भारमुक्त किया जाता है।
- राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन/ट्रांसमिशन/डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल आफ एसोसिएशन की कंडिका-77 (i) एवं कंडिका-92 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. रोहित यादव, भा.प्र.से. (2002) को पदभार ग्रहण करने की तारीख 04-10-2024 से आगामी आदेश पर्यन्त अस्थायी रूप से उक्त कंपनियों में निदेशक एवं अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कोशले, उप-सचिव।

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 13 दिसम्बर 2024

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/17552/क/भू-अर्जन/202210050400020 अ 82/2022.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	बरपाली	चिचोली	0.105 हे.	मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना के अंतर्गत चाम्पा शाखा नहर के कचोरा माईनर नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 17-01-2025 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम चिचोली नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना के अंतर्गत चाम्पा शाखा नहर के कचोरा माईनर नहर निर्माण
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	03
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	— लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	सिंचाई की सुविधा
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत वसंत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2020-21/3221.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गौरेला-पेण्ड्रा- मरवाही	मरवाही	देवरीडांड प.ह.नं.-22	0.585	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड.	राजाडीह जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मरवाही के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लीना कमलेश मंडावी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

कोरबा, दिनांक 20 दिसम्बर 2024

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17871/202208050400015/अ-82/2021-22/2024.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	दीपका	रंगबेल प.ह.नं.-60	2.847	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ./स.) कोरबा संभाग, कोरबा.	हरदीबाजार - तरदा - सर्वमंगला-इमलीछापर मार्ग लं. 27.19 कि.मी. में सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 20 दिसम्बर 2024

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17878/202208050400020/अ-82/2021-22/2024.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	दीपका	भर्राकुड़ा प.ह.नं.-54	2.591	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ./स.) कोरबा संभाग, कोरबा.	हरदीबाजार - तरदा - सर्वमंगला-इमलीछापर मार्ग लं. 27.19 कि.मी. में सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 20 दिसम्बर 2024

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17884/202208050400022/अ-82/2021-22/2024.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	दीपका	गंगदेई प.ह.नं.-55	3.409	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ./स.) कोरबा संभाग, कोरबा.	हरदीबाजार - तरदा - सर्वमंगला-इमलीछापर मार्ग लं. 27.19 कि.मी. में सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 20 दिसम्बर 2024

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17887/202302050400004/अ-82/2022-23/2024.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	जवाली प.ह.नं.-02	0.048	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	दीपका - जवाली - चाकाबुड़ा मार्ग में खोलार नाला पर उच्चस्तरीय पुल के पहुंच मार्ग निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 20 दिसम्बर 2024

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17894/202208050400019/अ-82/2021-22/2024.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	दीपका	अखरापाली प.ह.नं.-54	2.897	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ./स.) कोरबा संभाग, कोरबा.	हरदीबाजार - तरदा - सर्वमंगला-इमलीछापर मार्ग लं. 27.19 कि.मी. में सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 20 दिसम्बर 2024

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17902/202208050400018/अ-82/2021-22/2024. —चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	दीपका	मुढ़ाली प.ह.नं.-53	1.178	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ./स.) कोरबा संभाग, कोरबा.	हरदीबाजार - तरदा - सर्वमंगला-इमलीछापर मार्ग लं. 27.19 कि.मी. में सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 20 दिसम्बर 2024

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17905/202208052900183/अ-82/2021-22/2024. —चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	दीपका	नवापारा प.ह.नं.-52	1.863	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ./स.) कोरबा संभाग, कोरबा.	हरदीबाजार - तरदा - सर्वमंगला-इमलीछापर मार्ग लं. 27.19 कि.मी. में सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 20 दिसम्बर 2024

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17908/202208050400021/अ-82/2021-22/2024.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	दीपका	दर्री प.ह.नं.-54	1.329	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ.स.) कोरबा संभाग, कोरबा.	हरदीबाजार - तरदा - सर्वमंगला-इमलीछापर मार्ग लं. 27.19 कि.मी. में सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 20 दिसम्बर 2024

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17911/202208050400017/अ-82/2021-22/2024.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	दीपका	बिरदा प.ह.नं.-55	3.188	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ.स.) कोरबा संभाग, कोरबा.	हरदीबाजार - तरदा - सर्वमंगला-इमलीछापर मार्ग लं. 27.19 कि.मी. में सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 20 दिसम्बर 2024

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17914/202208050400014/अ-82/2021-22/2024. —चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	दीपका	भलपहरी प.ह.नं.-60	2.375	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ./स.) कोरबा संभाग, कोरबा.	हरदीबाजार - तरदा - सर्वमंगला-इमलीछापर मार्ग लं. 27.19 कि.मी. में सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 20 दिसम्बर 2024

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17945/202208050400016/अ-82/2021-22/2024. —चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	दीपका	कटकीडबरी प.ह.नं.-52	1.803	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ./स.) कोरबा संभाग, कोरबा.	हरदीबाजार - तरदा - सर्वमंगला-इमलीछापर मार्ग लं. 27.19 कि.मी. में सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत वसंत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कोण्डागांव, छत्तीसगढ़
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व
एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोण्डागांव, दिनांक 3 दिसम्बर 2024

क्रमांक/6365/202405200900058/अ-82/भू-अर्जन/2023-24.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-कोण्डागांव
- (ख) तहसील-मर्दापाल
- (ग) नगर/ग्राम-कुधूर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.060 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
154	0.060
योग	01 0.060

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम-कुधूर, तहसील-मर्दापाल भू-अर्जन अन्तर्गत कुधूर-तुमडीवाल मार्ग पर भंवरडीह नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कुणाल दुदावत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 20 दिसम्बर 2024

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/17898/202010050400004 अ 82/2024.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-उरगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.125 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
227/4	0.012
290/1	0.009
432/8/छ	0.020
433/1	0.069
429/6	0.015
योग	05 0.125

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चाम्पा-गेवरा रेलमार्ग के कि.मी. 694/31-33 पर (उरगा के पास) रेलवे ओव्हर ब्रिज के पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत वसंत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व
एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 20 दिसम्बर 2024

क्रमांक/1638/अ-82/2024.— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15(1) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा-15(2) के अन्तर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की परसा ईस्ट केते बासेन कोल परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पतियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-उदयपुर
(ग) नगर/ग्राम-घाटबर्वा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-54.322 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
336/1	0.170, 0.220
336/1	0.312
336/1	0.150
873/1	0.320
1/1	0.270
308/1	0.290
336/1	0.405
336/1	0.300
496/1	0.809
1/1	1.620
1/1	2.025
1/1	0.405
1/1	0.405
P-2004	1.027
P-2004	0.808
P-2004	0.520

(1)	(2)
P-2004	1.015
P-2004	0.437
P-2004	1.000
P-2004	0.400
P-2004	0.243
P-2004	0.800
P-2004	0.718
P-2005	1.311
P-2005	0.906
P-2005	0.906
P-2005	0.906
1/1	1.000
1/1	0.405
308, 496/1	0.524
308/1	1.620
384/1	0.405
102/1	0.024
P-2005	0.120
P-2004	0.364
P-2002	1.080
P-2002	0.720
P-1998	0.240
P-2004	0.090
P-2002	1.800
P-1998	1.000
P-1998	0.360
P-1998	0.640
P-1998	2.004
P-1998	0.320
P-1998	1.000
P-2004	0.307
P-2004	2.000
P-2004	0.405
P-2004	1.133
P-2004	1.570
P-2004	1.263
P-2004	0.186
P-2005	0.800
P-2004	0.350
P-1998	0.400
P-2005	0.240
P-2005	0.450
P-2004	0.150
P-2004	0.150
P-2004	0.350
P-2002	0.378
P-2004	0.450

(1)	(2)	अनुसूची	
P-2004	0.450	(1) भूमि का वर्णन-	
P-2004	0.360	(क) जिला-दंतेवाड़ा	
P-1998	0.238	(ख) तहसील-दंतेवाड़ा	
P-2005	0.300	(ग) नगर/ग्राम-पातररास	
P-2005	0.400	(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.770 हेक्टेयर	
P-2005	0.800	आक्षेप का निराकरण	
P-2005	1.500	उपरान्त भूमि का क्षेत्रफल-0.9901 हे.	
P-2005	1.000	खसरा नम्बर	रकबा
P-2005	1.000		(हेक्टेयर में)
P-2004	0.480	(1)	(2)
P-2004	0.150	निजी	
P-2004	0.350	63	0.120
P-1998	0.242	65/1	0.190
P-1998	0.240	65/3,	0.0085
P-2004	0.216	65/4	0.160
P-2002	0.710	65/5	0.158
P-2005	2.000	65/6	0.0768
P-1998	0.350	65/10	0.0512
P-2004	0.360	65/12	0.200
P-2005	0.180	65/14	0.0256
योग	82	योग	09
	54.322		0.9901

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-परसा ईस्ट केते बासेन कोल परियोजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उदयपुर, जिला-सरगुजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलास भोसकर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व
एवं आपदा प्रबंधन विभाग

दंतेवाड़ा, दिनांक 31 दिसम्बर 2024

क्रमांक/7378/भू-अर्जन/2024.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

शासकीय भूमि	
59	0.150
68	0.620
योग	02
	0.770

वृक्ष का किस्म	संख्या
महुआ	01
सागौन	03
आम	02
साजा	04
हल्लु	02
बीजा	03
जामुन	01
अन्य	01
धावड़ा	01

योग 18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बायपास गीदम जनपद से बांगाबाड़ी सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दंतेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक चतुर्वेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
“सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन” सेक्टर-24, कयाबांधा, अटल नगर, नवा रायपुर

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 18 नवम्बर 2024

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./टी.एल./2024-25/5179.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2023-24/6160-6161 दिनांक 15-12-2023 द्वारा श्री दिनेश कुमार ब्यौहार उपसंचालक कृषि, मुंगेली, जिला-मुंगेली को कृषि उपज मंडी समिति मुंगेली, जिला-मुंगेली का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया है।

सचिव कृषि उपज मंडी समिति मुंगेली, जिला-मुंगेली का पत्र क्रमांक/मंडी/लेखा/2024-25/732 दिनांक 10-10-2024 द्वारा अवगत कराया है कि कृषि उपज मंडी समिति के भारसाधक अधिकारी श्री दिनेश कुमार ब्यौहार उप संचालक कृषि, मुंगेली का स्थानांतरण छ.ग. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था रायपुर होने का उल्लेख करते हुए श्री एम.आर.तिग्गा, उपसंचालक, कृषि मुंगेली जिला-मुंगेली का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्री दिनेश कुमार ब्यौहार उप संचालक कृषि, मुंगेली जिला-मुंगेली के स्थान पर श्री एम.आर. तिग्गा, उप-संचालक, कृषि मुंगेली जिला-मुंगेली को कृषि उपज मंडी समिति मुंगेली, जिला-मुंगेली का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

महेन्द्र सिंह सवन्नी,
संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 8th October 2024

No. 16600/Checker/III-6-2/2007 (Pt.-I).—In exercise of the powers Conferred under clause (b) of sub-section (1) of Section 283 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the High Court of Chhattisgarh hereby specially empowers the following Judicial Magistrate First Class to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section :—

Sl. No.	Name of the Judicial Magistrate First Class	Present place of posting	Civil District
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Shri Manjeet Jangde, J.M.F.C., Korba	Korba	
2.	Smt. Richa Yadav, J.M.F.C., Korba	Korba	Korba
3.	Shri Siddharth Anand Soni, J.M.F.C., Katghora	Katghora	

By order of the High Court,
BALRAM PRASAD VERMA, Registrar General.